दिनांक 22.10.2011 को विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद में माननीय प्रशासक महोदय का अभिभाषण

~~~~~~

परम आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय जी, माननीय गृह मंत्री महोदय जी, माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, सभी राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रीगण, सभी संघ प्रदेशों के माननीय प्रशासकगण, भारत सरकार के सचिवगण, मुख्य सचिवगण, सचिवगण और इस बैठक में उपस्थित अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीगण;

2. 12वीं पंच वर्षीय योजना के लिए उत्कृष्ट ड्राफ्ट एप्रोच पेपर तैयार करने के लिए संघ प्रदेश प्रशासन, योजना आयोग, भारत सरकार का आभारी है । हमें विश्वास है कि ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यह शानदार वृद्धि का अग्रदूत सिद्ध होगा। इससे हमारा राष्ट्र शहरीकरण, ग्रामीण विकास संबंधी परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन एवं समग्र विकास से जुडे सभी मुद्दों संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम होगा।

3. दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली हमारे देश के पश्चिमी भाग में स्थित दो छोटे संघ प्रदेश हैं । जब ये प्रदेश वर्ष 1961 में भारत के अंग बन गये, तब इन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारे देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था । भारत सरकार ने वर्ष 1980 के उत्तरार्ध में इन संघ प्रदेशों के लिए करों में कुछ छूट की घोषणा की । उसके बाद इन प्रदेशों में अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ, और बाद में गरीबी दर, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर, शिशु पोषण, गर्भवती एवं स्तनपान करानेवाली माताओं आदि के स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विकास के सूचकों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई । वर्तमान में ये सभी सूचक राष्ट्रीय स्तर से काफी ऊपर हैं । इन सामाजिक एवं आर्थिक सूचकों में और अधिक सुधार के लिए हमारा प्रशासन प्रतिबद्ध है ।

4. योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में दमण एवं दीव के लिए 900 करोड रूपये तथा दादरा एवं नगर हवेली के लिए 1300 करोड़ रूपये का अनुमोदन किया था । परंतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक आबंटन कम हुआ । इसके अंतर्गत दमण एवं दीव के लिए **850** करोड़ रूपये और दादरा एवं नगर हवेली के लिए **991** करोड़ रूपये आबंटित किये गए । 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान आबंटित योजना मद् का लगभग 100% हम खर्च कर पाये हैं । माननीय महोदय, मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि दोनों ही संघ प्रदेशों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के विगत चार वर्षों में चालू राजस्व शेष राशि (B.C.R.) धनात्मक रहा है । हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी हम धनात्मक
~~~~~~

चालू राजस्व शेष राशि (B.C.R.) दे पायेंगे । यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में दोनों संघ प्रदेशों के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि का ठोस आधार है । चूँकि

इन संघ प्रदेशों में विधायिका नहीं है, अतः संघ प्रदेश प्रशासन निधि के आबंटन हेतु पूरी तरह से भारत सरकार पर निर्भर है । इन प्रदेशों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप फंड का आबंटन भी नहीं किया गया है । प्रदेश में औद्योगिक विकास बनाये रखने के लिए तथा इन प्रदेशों में पर्यटन की संभावनाओं को पूरी तरह से तलाशने के लिए आधारभूत संरचना में सुधार की नितांत आवश्यकता है ।

5. जैसा की मैंने पहले कहा है, अस्सी के दशक में करों में छूट की घोषणा के बाद औद्योगिक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है । अब, जबकि कर छूट की अवधि समाप्त होने जा रही है, अधिकतर औद्योगिक ईकाईयाँ असमंजस की स्थिति में है । ये ईकाईयाँ तृप्तता बिन्दु (**Saturation Point**) पर पहुँच गई है और इसलिए अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए उनमें विस्तार की आवश्यकता है । इन औद्योगिक ईकाईयों द्वारा हजारों, करोड़ रूपये के पूँजी निवेश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है । कर में छूट न होने की स्थिति में बिजली, जलआपूर्ति एवं परिवहन से जुड़ी आधारभूत संरचना में सुधार के द्वारा ही प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की जा सकती है ।

6. माननीय महोदय, औद्योगिकीकरण के कारण इन संघ प्रदेशों में अ-योजनाबद्ध शहरीकरण हुआ है । निधि के अभाव के कारण शहरी आधारभूत संरचना में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई है । इन दोनों संघ प्रदेशों के किसी भी शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार की योजनाबद्ध जल निकास व्यवस्था नहीं है । हमने सभी शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जलनिकास व्यवस्था तथा जलापूर्ति के लिए व्यापक योजना तैयार की है ।

7. सिलवासा के म्यूनिसिपल क्षेत्र की जलआपूर्ति परियोजना कई वर्षों से शहरी विकास मंत्रालय में स्थाई वित्तीय समिति से **Clearnce** न मिलने के कारण लंबित थी । हम शहरी विकास मंत्रालय के आभारी है कि उन्होंने हमारी परियोजना को मंजूरी दे दी है । **UIDSSMT** के अंतर्गत इस परियोजना की शुरूआत वर्ष 2006 में की गई थी, परंतु तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय मंजूरी में प्रक्रियागत विलंब के कारण परियोजना लागत को दो बार परिशोधित करना पडा था । दमण नगरपालिका क्षेत्र की दूसरी महत्वकांक्षी जलापूर्ति परियोजना भी ग्रामीण विकास मंत्रालय में लंबित थी । इसे भी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है । इस परियोजना के अंतर्गत मधुबनडैम से पाईपलाईन के जरिए जल आपूर्ति दमण के विभिन्न जलशोधन सयंत्रों में की जायेगी । इस परियोजना की लागत 45 करोड़ से अधिक है ।

8. दीव एक सुंदर द्वीप है । यहाँ बरसात कम होने के कारण जलापूर्ति की समस्या है । इस क्षेत्र में भूमिगत जल <u>500</u> फिट नीचे चला गया है । सरदार सरोवर डैम से पाईपलाईन के जरिए दीव जिले में जलापूर्ति का हमारा प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों से शहरी विकास मंत्रालय में

विचाराधीन है । इस परियोजना की लागत लगभग 32 करोड़ है और यह पेय जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में **SFC** Clearance हेतु लंबित है ।

9. हमें आशा है कि इन परियोजनाओं को लागू किये जाने से हम इन दोनों संघ प्रदेशों में पेयजल की माँग को पूरा कर पायेंगे । जल आपूर्ति की समस्या से समुचित रूप से निपटने के लिए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली हेतु एक व्यापक अध्ययन कराया गया है । इस एकीकृत जल प्रबंधन योजना को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित करने में लगभग 125 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी । यदि इस योजना को लागू किया जाता है, तो वर्ष **2040** तक संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में तथा औद्योगिक इकाईयों के उपयोग हेतु पेय जल की समस्या से निजात पायी जा सकेगी । इन सभी परियोजनाओं के लिए हमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में दादरा एवं नगर हवेली के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये की और दमण एवं दीव के लिए लगभग 100 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी ।

10. महोदय, हमारे प्रदेश में बिजली उत्पादन की अपनी व्यवस्था नहीं है । हमारी बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय सेक्टर के बिजली उत्पादन केंद्रों से होती है । **Peak Hours** के दौरान दादरा एवं नगर हवेली को 567 मेगावाट और Off -Peak Hours के दौरान 483 मेगावाट बिजली आबंटित की जाती है । Peak Hours के दौरान दमण को 252 MW और Off -Peak Hours के दौरान 274 मेगावाट बिजली आबंटित की जाती है । इन संघ प्रदेशों के लिए 170 मेगावाट बिजली आबंटन हेतु NSPCL, भिलाई के साथ हमारा द्विपक्षीय करार है । परंतु वर्तमान बिजली आबंटन की वर्तमान व्यवस्था उद्योगों की कुल आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है । हमने कई बार इस मामले को विद्युत मंत्रालय के समक्ष रखा है । माननीय गृह राज्यमंत्री भी इस मुद्दे को समय-समय पर उठाते रहे हैं, परंतु अब तक इस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं देखा गया है । मैं यह भी कहना चाहूँगा कि दोनों ही संघ प्रदेशों में **T & D loss** करीब 8 % के आस पास है, जो कि देश में सबसे न्यूनतम **T & D loss** में से एक है । औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लगभग 04 रूपये प्रति यूनिट बिजली के लिए हमारी टैरिफ दर तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 02 रूपये प्रति यूनिट बिजली पश्चिम क्षेत्र में न्यूनतम टैरिफ दरों में एक है । अत्यंत निम्न टैरिफ दरों के बावजूद हम बिजली के वितरण के जरिए अतिरिक्त लाभ कमा रहे हैं और भारत की समेकित निधि में ठोस रूप से योगदान दे रहे हैं । वर्ष 2010-11 के दौरान हमने 161 करोड़ रूपये से ज्यादा का योगदान दिया है ।

11. हमारी औद्योगिक ईकाईयों की बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक बहुमुखी रणनीति पर काम कर रहे हैं । एक ओर हम अल्पकालिक एवं मध्यकालिक बिजली खरीद संबंधी करारों के जरिए बिजली प्राप्त करने

की कोशिश कर रहे हैं, वही दूसरी ओर बिजली आपूर्ति समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु नवसारी में 1320 MW की बिजली परियोजना स्थापित करने हेतु हमने गुजरात सरकार के साथ करार किया है । इस उद्देश्य के लिए हम दादरा एवं नगर हवेली में विद्युत विभाग के निगमीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं । हाल ही में हमें गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है । परंतु हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद गुजरात सरकार ने हमें अभी तक भूमि आबंटित नहीं की है । इस ऐतिहासिक मंच के जरिए मैं एक बार फिर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रस्तावित विद्युत सयंत्र की **Public Private Partnership (PPP)** आधार पर स्थापना हेतु जमीन के आबंटन के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का पुनःअनुरोध करता हूँ । इस वर्ष जून महीने में योजना आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से इस योजना के लिए अपनी सहमति प्रदान की है । इसके लिए मैं योजना आयोग का आभारी हूँ ।

12. महोदय यदि हम **PPA** के जरिए बिजली प्राप्त करने की स्थिति में हैं, तो भी हमें अपनी **T & D** व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि बिजली के अतिरिक्त लोड को उपभोक्ताओं तक पूरी दक्षता के साथ पहुँचाया जा सके । हमें मौजूदा विद्युत उप केंद्रों तथा वितरण लाइनों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है और विशेष रूप से नई वितरण लाइन लगवाने की जरूरत है । साथ ही, टी एवं डी घाटों को और कम करने की आवश्यकता है । इसके लिए हम शहरी क्षेत्रों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भूमिगत केबल लगवाने की योजना बना रहें हैं । 11वीं योजना के दौरान दमण के कुछ क्षेत्रों में पहले ही यह कार्य कर लिया गया है । बिजली के क्षेत्र में हमारी योजनाओं और चालू कार्यों पर विचार करते हुए, हम दादरा एवं नगर हवेली के लिए 400 करोड़ रूपये और दमण एवं दीव के लिए 250 करोड़ रूपये के फंड 12वीं पंचवर्षीय योजना में सुरक्षित रखे जाने का अनुरोध करते हैं, जिससे कि इन दोनों प्रदेशों में आधारभूत बिजली संरचना तथा संबन्धित सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके ।

13. महोदय, हमारे प्रदेश में सड़क संबंधी आधारभूत संरचना अपर्याप्त है, जो कि औद्योगिक विकास के लिए दूसरी सबसे बड़ी बाधा है । दुर्भाग्यवश भारत संघ के साथ एक हो जाने के बाद से आज तक, इन संघ प्रदेशों में से कोई भी क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है । मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ाव हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है । प्रस्तावित मार्ग गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से गुजरेंगे । राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से दमण तक सड़क का कुल विस्तार लगभग

30 किलोमीटर होगा और दादरा एवं नगर हवेली के लिए यह विस्तार 33 किलोमीटर होगा । मैं महाराष्ट्र एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इसके लिए गृह मंत्रालय को अनापत्ति प्रमाणपत्र दें, ताकि इन प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा सके । दादरा एवं नगर हवेली के प्रस्तावित राजमार्ग कनेक्टिवीटी थाने जिले की आदिवासी जनता के लिए अत्यंत लाभदायक होगा । इसी प्रकार दमण के लिए प्रस्तावित कनेक्टिवीटी से वापी शहर में यातायात की भीड-भाड काफी हद तक कम हो जायेगी । हमें आशा है कि इस उद्देश्य के लिए 12वीं योजना में पर्याप्त प्रावधान किये जायेंगे ।

14. दादरा एवं नगर हवेली के नगरीय क्षेत्र में काफी लंबे समय से एक रिंग रोड के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जहाँ पिछले दशक में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है । यह प्रस्ताव पिछले 14 वर्षों से रूका पड़ा है । मैं योजना आयोग का आभारी हूँ, जिन्होंने इस परियोजना को इस वर्ष जून महीने में वर्किंग ग्रुप की चर्चा के दौरान अनुमोदन दिया है । इस सड़क का कुल विस्तार लगभग 11.30 कि.मी. होगा । हम इसके लिए भूमि हासिल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं । हमें भूमि हासिल करने के लिए लगभग 75 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी और सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए भी करीब इतने ही रूपयों की आवश्यकता होगी । साथ ही, हमें दोनों संघ प्रदेशों में सड़क नेटवर्क को सुधारने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में हैं । अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब है ।

इसलिए सभी मौसम में अच्छी कनेक्टिविटी बनाये रखने के लिए हमने मौजूदा सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और नयी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है । साथ ही हमने विभिन्न नदियों पर 19 पुलों के निर्माण, जिसमें दमणगंगा नदी पर एक केवल स्टेड पुल का निर्माण भी शामिल है, की योजना बनाई है । हमें इस उद्देश्य के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संघ प्रदेश दमण एवं दीव के लिए 500 करोड़ रूपये तथा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के लिए 600 करोड़ रूपये के आबंटन की आवश्यकता होगी ।

15. 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा सामाजिक संयोजन के साथ-साथ जीविका के बेहतर अवसरों के निर्माण पर जोर दिया गया है । इन दोनों संघ प्रदेशों में औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा रोजगार के अनेक अवसर सृजित किये गये हैं । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ज्यादातर उद्योग अब अपने सैचुरेशन बिन्दु पर हैं । इसलिए हमें स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु अन्य क्षेत्रों की तलाश करनी होगी, क्योंकि शिक्षा के प्रसार के कारण उनकी महत्वकांक्षाओं का स्तर भी बढ़ रहा है । इन

दोनों संघ प्रदेशों में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं । परंतु यह बेहतर कनेक्टिविटी पर निर्भर होगा । हम योजना आयोग के आभारी हैं जिन्होंने हमें दादरा एवं नगर हवेली के लुहारी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है और चालू वार्षिक योजना में इसके लिए टोकन प्रावधान भी किया है । परंतु इस प्रोजेक्ट को PPP (Public Private Patrnership) आधार पर तभी लागू किया जा सकता है, जब प्रशासन द्वारा इसके लिए भूमि हासिल कर ली जाए । हमें भूमि हासिल करने के लिए पर्याप्त फंड की आवश्यकता होगी । इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रूपये की राशि दी जाए । हम मधुबन डैम के नजदीक दुधनी के सुंदर पहाडी क्षेत्र में PPP आधार पर एक विशाल पर्यटन पार्क के निर्माण की भी योजना बना रहे हैं । इस परियोजना के लिए भी भूमि हासिल करने हेतु 100 करोड़ रूपये फंड की आवश्यकता होगी ।

16. महोदय, दीव सफेद रेतों वाला एक सुंदर द्वीप है और सोमनाथ मंदिर, गीर वन, जूनागढ़ और दिलवाड़ा और जैन मंदिरों के नजदीक है । दीव को जूनागढ सर्किट का हिस्सा बनाने के लिए हमने यह मामला गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग के समक्ष पहले ही उठाया है । परंतु दीव की वास्तविक पर्यटन क्षमता तभी विकसित हो सकेगी, जब दीव को रेल मार्ग से जोड़ा जाय । इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे रेल लाईन को वेरावल से घोघला तक विस्तारित करें । दमण के पश्चिमी समुद्रतटीय क्षेत्र में सुंदर तट हैं । यदि दमण एवं दीव को समुद्री रास्ते से जोड दिया जाय, तो समुद्र आधारित पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है । हम योजना आयोग के आभारी हैं जिन्होंने इस वर्ष दमणगंगा नदी के मुहाने से रेत निकालने के हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है । इसके लिए वार्षिक योजना में टोकन प्रावधान भी किया गया है । इस परियोजना के लिए हमें 100 करोड़ रूपये की आवश्यकता है । हम एक छोटा बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि निकाले गये रेत का बेहतर उपयोग किया जा सके । इससे हम पर्यटन संबंधी जहाजों को रखने में समर्थ हो सकेंगे, ताकि दमण एवं दीव के बीच में आवागमन शुरू हो सके । इस उद्देश्य के लिए हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रूपये के फंड के प्रावधान हेतु अनुरोध करते हैं ।

17. दोनों संघ प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है । ज्यादातर क्षेत्रों में कम वर्षा होती है । बहुत कम और टुकडों में बँटी हुई कृषि भूमि, रसायनों एवं उर्वरकों का आवश्यकता से कम प्रयोग, कृषि पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति जैसी सामान्य समस्या कृषि के क्षेत्र में व्याप्त हैं । सिंचाई की भी संभावनाएं सीमित हैं । मौजूदा सिंचाई क्षमता हमें मधुबन डैम से उपलब्ध है और नहर

व्यवस्था की सही देखभाल के अभाव में इसका भी समुचित उपयोग गुजरात सरकार के कृषि विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है । अब नहरों की मरम्मत एवं देखभाल का कार्य हम स्वयं ही कर रहे हैं । सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने, नहर बनाने एवं नहरों की मरम्मत और रख-रखाव हेतु हमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दमण एवं दीव के लिए लगभग 40 करोड़ रूपये ओर दादरा एवं नगर हवेली के लिए 60 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी । हम किसानों को बागवानी से संबन्धित फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं । मिट्टी एवं जल के संरक्षण एवं उच्च स्तर की पैदावार वाले बीजों की किस्म प्रयोग करने के लिए भी हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं । हम अग्रणी बैंकों से संपर्क करते हुए इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को 100 प्रतिशत शामिल किया जाय । परंतु ये सारे प्रयास आज के युवा एवं शिक्षित जनसंख्या की नौकरी की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस समस्या का सही समाधान हमारी पर्यटन क्षमता को पूरी तरह विकसित करने में है ।

18. महोदय, हम भारत सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हमने बहुत सी स्कीमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार किये हैं । इसका मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, दादरा एवं नगर हवेली में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान लाभार्थियों की संख्या मात्र 902 थी, जो अब बढ़कर 5000 से अधिक हो गई है । इसी प्रकार दमण एवं दीव में लाभार्थियों की संख्या 1207 से बढ़कर 2536 हो गई है । हम साथ ही साथ वित्तीय वृद्धि भी सुनिश्चित कर रहे हैं । दादरा एवं नगर हवेली के सभी लाभार्थियों के लिए नो-फ्रिल बैंक खाता खोला गया है । यह राशि ECS के जरिए सीधे उनके खातों में जमा कर दी जाती है । गरीब अशिक्षित आदिवासी लाभार्थी अपने गाँव में बैंक के Correspondent के जरिए अपने घर पर ही यह राशि प्राप्त कर सकते हैं । यही कार्य वर्तमान में दमण एवं दीव में भी किया जा रहा है और हमें आशा है कि यह कार्य एक महीने के भीतर पूरा कर लिया जायेगा । हमारा लक्ष्य है कि पात्रता रखनेवाले सभी व्यक्तियों को इसके अंतर्गत शत-प्रतिशत शामिल किया जाय । साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम क्रियात्मक एवं मनोरंजन से संबंधित सेवाओं सहित उनके लिए वृद्धाश्रम आवासों के निर्माण की योजना बना रहे हैं । वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती औसत आयु को ध्यान में रखते हुए हम वरिष्ठ नागरिकों और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीमों को लागू करने की योजना बना रहे हैं । 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन

सभी स्कीमों को लागू करने के लिए संघ प्रदेश दमण एवं दीव के लिए 300 करोड़ रूपये तथा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के लिए 400 करोड़ रूपये के अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता है ।

19. महोदय, शिक्षित नागरिक राष्ट्र की संपत्ति हैं । हमारा प्रयास है कि हम दोनों संघ प्रदेशों में शिक्षा अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करें । सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान में हमारा कार्य अनुकरणीय रहा है । हमें गर्व है कि दादरा एवं नगर हवेली ने वर्ष 2011 के लिए दशक का साक्षरता पुरस्कार प्राप्त करके संघ प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलायी है । मुक्ति के 57 वर्षों बाद भी दादरा एवं नगर हवेली में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था । इस वर्ष हमने वहाँ उच्चतर शिक्षा हेतु सिलवासा संस्थान के नाम से एक सरकारी कॉलेज की स्थापना की है, जिसमें कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय हैं । कॉलेज का भवन तैयार हो जाने पर हम नये संकायों की शुरूआत करने की भी योजना बना रहे हैं। माननीय गृह राज्यमंत्री, श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन जी ने 25 जुलाई, 2011 को मौजूदा स्कूल भवन में इस कॉलेज का उदघाटन किया था । उन्होंने कॉलेज भवन के साथ-साथ ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखी थी । हमारी एक आर्ट कैंपस के निर्माण की भी इच्छा है, जिसमें 2000 छात्रों को दाखिला मिल सकेगा । इस उद्देश्य के लिए हमें 80 करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता होगी । हमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के वास्तविक आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने और विस्तारित करने की आवश्यकता है । इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम दादरा एवं नगर हवेली के लिए 350 करोड़ रूपये तथा दमण एवं दीव के लिए 200 करोड़ रूपये की राशि दिये जाने का अनुरोध करते हैं ।

20. महोदय, जैसे शिक्षित व्यक्ति राष्ट्र की धरोहर है इसी प्रकार राष्ट्र के समग्र विकास के लिए स्वस्थ व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है । दोनों ही संघ प्रदेशों में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया है । हमने दादरा एवं नगर हवेली के श्री विनोबाभावे सिविल अस्पताल और दमण के भी सिविल अस्पताल में अद्यतन चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराई हैं । दीव में एक नए चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त दादरा एवं नगर हवेली में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत अति आधुनिक बाह्य रोगी विभाग (OPD) ब्लॉक सहित 200 बिस्तरो वाला सुविधा संप्न्न एवं आधुनिक चिकित्सालय के निर्माण करने की योजना है । योजना आयोग द्वारा इसका अनुमोदन पहले ही दिया जा चुका है और टोकन प्रावधान भी किया जा चुका है । हमारी डिजाइन तैयार हैं और इसे तकनीकी एवं वित्तीय क्लीयरेन्स प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जायेगा । इस

परियोजना में भवन निर्माण हेतु 100 करोड़ रूपये तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए 80 से 90 करोड रूयपे की परियोजना लागत आयेगी । इसलिए हमारा अनुरोध है कि दादरा एवं नगर हवेली के लिए लगभग 200 करोड और दमण के वर्तमान सिविल चिकित्सालय के उन्नयन एवं विस्तार के लिए और 100 करोड का 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया जाय ।

21. महोदय, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का मैंने विस्तार से उल्लेख किया । हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना फंड के अंतर्गत दमण एवं दीव के लिए 2500 करोड तथा दादरा एवं नगर हवेली के लिए 3500 करोड रूपये का अनुमान लगाया है ।

22. महोदय, मैं कुछ प्रशासनिक समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन संघ प्रदेशों के लिए उपयुक्त एवं सक्षम मंत्रालय है । इस अधिनियम के सही एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ प्रदेशों के प्रशासक को उपयुक्त एवं सक्षम प्राधिकार दिये जाने की आवश्यकता है । महोदय, इन संघ प्रदेशों की समग्र साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत दर से अच्छी है, फिर भी हम तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं । हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इन संघ प्रदेशों के छात्रों के लिए MBBS और इंजीनियरिंग की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं, ताकि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र कमी को पूरा किया जा सके । वर्तमान में हमारे यहाँ कोई मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है । परंतु दोनों संघ प्रदेशों के मौजूदा पॉलिटेक्निक को पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में विकसित करने का हमारा प्रस्ताव है, ताकि आसानी से योग्य प्राध्यापक भर्ती किये जा सकें और सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन भी किया जा सके । वर्तमान में हमारे इस कार्य में बाधा आ रही है क्योंकि हम अपने स्तर पर न तो भर्ती नियम बना सकते हैं, न ही संशोधित कर सकते हैं और न, ही हम प्राध्यापक भर्ती कर सकते हैं ।

23. महोदय, हम महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा में बडी संख्या में रिक्त पदों को नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि भर्ती नियम बनाने या संशोधन हेतु हमारे प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग अथवा संबन्धित मंत्रालय के पास लंबित पडे हैं । हमारा नम्र अनुरोध है कि समूह **'क'** एवं **'ख'** के राजपत्रित पदों के अनुमोदन का प्राधिकार इन संघ प्रदेशों के प्रशासक को प्रत्यायोजित की जाय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए नये पदों के सृजन पर लगी रोक तुरंत हटाई जाय ।

24. दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा योजनागत स्कीमों के लिए वित्तीय मंजूरी हेतु प्रशासक को वित्तीय प्राधिकार प्रदान करने का है । वर्तमान में प्रशासक 20 करोड़ रूपये तक की परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी प्रदान कर सकते हैं । 20 करोड रूपये से अधिक की हमारी सभी परियोजनाओं को संबन्धित मंत्रालय से क्लीयर कराना होता है । एक बार कोई प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाता है, तो वह प्रक्रियात्मक उलझन में फँस जाता है । मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी जल आपूर्ति परियोजना को SFC क्लीयरेन्स पाने में कई वर्ष लग गये । चूँकि, हम जिन परियोजनाओं की अब योजना बना रहे हैं उनमें से अधिकतर परियोजनाएं 20 करोड रूपये की सीमा से अधिक की हैं । इसलिए निवेदन है कि, वित्तीय शक्ति नियमावली, 1978 के नियम-18 के तहत वित्तीय प्राधिकार 20 करोड रूपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रूपये कर दी जाय । हमारा निवेदन है कि संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के लिए 50 करोड रूपये से अधिक कीमत वाली परियोजना स्कीम से संबन्धित व्यय मंजूरी प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग SFC गठित की जाए । इसके फलस्वरूप इन दोनों संघ प्रदेशों के लिए सभी बड़ी परियोजनाओं हेतु क्लीयरेंस एक सिंगल विंडो से ही मिल जायेगा । इससे इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर लागू किया जा सकेगा तथा इनमें अधिक समय लगने के कारण होनेवाली मूल्य वृद्धि से भी बचा जा सकेगा ।

25. महोदय, मैं दूसरी समस्या की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर वहेली में अपर्याप्त स्टाफ से संबन्धित है । यद्यपि संघ प्रदेश आकार की दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में सचिवालय स्तर पर कार्य लगभग समान है । वास्तव में पिछले दो दशकों में विकास की विभिन्न गतिविधियों में वृद्धि हुई है । जनसंख्या, औद्योगिक गतिविधियों, सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों जैसे कि- शिक्षा , स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण आदि में भी वृद्धि हुई है । मेरा गृह मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों से सादर अनुरोध है कि संघ प्रदेशों के सचिवालयों के साथ-साथ फील्ड विभागों में जैसे कि- स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन आदि के लिए नये पदों के सृजन की मंजूरी हेतु ध्यानपूर्वक विचार करने की कृपा करें ।

26. भारत सरकार के योजना आयोग ने दमण एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं योजना आयोग का हार्दिक आभारी हूँ । मेरे शब्दों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, भारत सरकार के सचिवगण, मुख्य सचिवगण तथा प्रशासकगण एवं इस बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारीगण को धन्यवाद देता हूँ । सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

- **जय हिन्द** -

राष्ट्रीय विकास परिषद
की
56वीं बैठक
22 अक्तूबर, 2011
विज्ञान भवन, नई दिल्ली
संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा
दादरा एवं नगर हवेली के
प्रशासक का अभिभाषण

श्री नरेन्द्र कुमार,
प्रशासक
संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा
दादरा एवं नगर हवेली

संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन
सचिवालय, मोटी दमण, दमण-396220